



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 26 मार्च, 2002/5 चंद्र, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्राधिसूचना

शिमला-171004, 26 मार्च, 2002

संख्या 1-25/2002-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथकर (सशोधन) विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक

---

संख्यांक-6) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,  
सचिव,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2002 का विधेयक संख्यांक 6

## हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2002 है ।

1975 का 9

2. हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन ।

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (क-क) और (क-ख) अन्तःस्थापित किए जाएंगे :—

“(क-क) “आयुक्त” से, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(क-ख) “पट्टेदार” से, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 3-क के अधीन पथकर का संग्रहण करने के अधिकार का पट्टा प्रदान किया गया है ;” और

(ख) खण्ड (च) में “अभिप्रेत है और” शब्दों के पश्चात् “,—” चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे और तत्पश्चात् आए शब्दों “पथकर के संग्रहण के बारे में बैरियर पर तैनात प्रत्येक सरकारी कर्मचारी इसके अन्तर्गत है ।” का लोप कर निम्नलिखित कोष्ठक, श्रृंखला, शब्द, चिह्न और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(i) पथकर के संग्रहण के बारे में बैरियर पर तैनात प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ; और

(ii) प्रत्येक पट्टेदार या धारा 3—क के अधीन पथकर के संग्रहण के लिए उस द्वारा उसके अभिकर्ता के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति, इसके अन्तर्गत है ।”

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा 3-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 3-क का अन्तःस्थापन ।

“3-क. पथकर का संग्रहण करने के अधिकार को पट्टे पर देने की राज्य सरकार की शक्ति .—

(1) राज्य सरकार, ऐसी तारीख से, जिसे यह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, ऐसी सड़क अवसंरचना पर गुजरने वाले यांत्रिक यानों

पर, किसी वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए नीलाम, निविदा या दोनों के संयोजन या किसी अन्य पद्धति द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन अवधारित करे, धारा 3 के अधीन उद्गृहीत पथकर का संग्रहण करने के अधिकार को किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पट्टा अनुदान के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पथकर की प्राप्तियों और पट्टा अवधि के लिए लागू पथकर की दरों को ध्यान में रखने के पश्चात् पट्टे की अवधि के दौरान बैरियर पर, संभाव्यतः वसूल किए जाने वाले पथकर की संकलित रकम का, निर्धारण करेगा।

(3) पट्टेदार से, पट्टे के निबंधनों और शर्तों की सम्यक् पूर्ति के लिए ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी, जैसी आयुक्त निर्दिष्ट करे।

(4) उप-धारा (1) के अधीन अनुदत्त पट्टे के अधीन किसी पट्टेदार द्वारा देय कोई राशि (शास्ति, ब्याज या कार्यवाहियों की लागत सहित) यदि नियत तारीख तक संदत्त नहीं की गई है, तो यह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

धारा 9 का  
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में, "यान्त्रिक यान को" शब्दों के पश्चात् आए शब्दों "निरुद्ध कर सकेगा या पथकर चुकाने के लिए पर्याप्त मूल्य के किसी माल या भार या बोझ के भाग का अभिग्रहण कर सकेगा और यदि पथकर संदत्त नहीं किया जाता है तो इसे बेच सकेगा।" के स्थान पर "तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि पथकर संदत्त नहीं कर दिया जाता है।" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10  
का लोप।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन, किसी सड़क अवसंरचना के उपयोग के लिए पथकर उद्गृहीत किया जाता है और इसे, सरकार द्वारा नियुक्त पथकर निरीक्षकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्थापित बैरियरों पर संगृहीत किया जाता है। पथकर का संग्रहण, चौबीस घण्टे किया जाना अपेक्षित है और इसके संग्रहण के लिए कर्मचारिवृन्द की अधिकतर सैकन्डमेन्ट आधार पर, विभिन्न स्त्रोतों से व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, पथकर के संग्रहण पर सारभूत व्यय और कर सम्बन्धी निगरानी पर सकेन्द्रण भी धीमा हो जाता है। इसलिए संग्रहण पद्धति को युक्तिसंगत बनाने के लिए पथकर के संग्रहण के कार्य को नीलाम, निविदा या किसी अन्य पद्धति, जो राजस्व हित में हो और जो राजस्व के वांछनीय प्रवाह को भी सुनिश्चित करे, द्वारा पट्टे पर देने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रवीण शर्मा,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख ..... 2002.

द्वितीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 6 of 2002.

## THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT) BILL, 2002

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Act, 2002.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

9 of 1975

(a) after clause (a), the following clauses (a-a) and (a-b) shall be inserted, namely:—

“(a-a) “Commissioner” means Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh;

(a-b) “lessee” means a person to whom the lease of the right to collect toll has been granted under section 3-A;” ; and

(b) in clause (f), after the words “and includes”, the sign “,—” shall be inserted and thereafter, for the words “every Government servant posted at a barrier in connection with the collection of toll”, the following brackets, figure, words, signs and letter shall be substituted, namely:—

(i) every Government servant posted at a barrier in connection with the collection of toll; and

(ii) every lessee or the person employed by him as his agent for collection of toll under section 3-A.”.

Insertion of section 3-A.

3. After section 3 of the principal Act, the following new section 3-A shall be inserted, namely:—

“3-A. *Power of the State Government to lease the right to collect toll.*—(1) The State Government may, with effect from such date as it may by notification specify, lease to any person the right to collect toll levied under section 3, on mechanical vehicles passing over any road infrastructure, by auction or tender or combination of both, or any other mode for any financial year or part thereof, on such terms and conditions as the Commissioner may, subject to approval of the State Government, determine.

(2) For the purposes of grant of lease under sub-section (1), the Commissioner shall, after taking into consideration the receipts of the toll for the preceding year or any part thereof and the rates of toll applicable for the lease period, assess aggregate amount of toll likely to be recovered at a barrier during the period of lease.

(3) The lessee shall be required to furnish such security for due fulfilment of the terms and conditions of the lease as the Commissioner may direct.

(4) Any sum (including penalty, interest or costs of the proceedings) payable by the lessee under a lease granted under sub-section(1), if not paid by the due date, shall be recoverable as arrears of land revenue.”.

4. In section 9 of the principal Act, for the words and sign “or seize any of the goods of part of burdern or load of sufficient value to defray the toll and sell the same, unless”, the word “until” shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 9.

5. Section 10 of the principal Act shall be omitted.

Omissi-  
on of  
section 10.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, a toll is levied for the use of any road infrastructure and it is collected by a Toll Inspector appointed by the Government at the barriers established for this purpose. The collection of toll is required to be done round the clock and the staff for its collection has been provided mostly on secondment basis from different sources. Besides, substantial expenditure on collection of toll and focus on tax related surveillance also gets diluted. Therefore, in order to rationalise the collection system, it has been decided to lease out the job of collection of toll by auction, tender, or any other mode, which may be in the revenue interest and which also ensure the desired flow of revenue. This has necessitated the amendment of the Act, *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

**PRAVEEN SHARMA,**  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :

Dated....., 2002.

## FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-